

रक्षा मंत्रालय ने 4106 करोड़ रुपये के रक्षा सौदों पर किए हस्ताक्षर

जीसैट-7सी और स्वदेशी टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद के लिए अनुबंध, नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता भी होगी मजबूत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए समर्पित संचार उपग्रह जीसैट-7सी और भारतीय नौसेना के लिए भारी वजन वाले स्वदेशी टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद के लिए कुल 4106 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सौदों से सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता मजबूत होगी और घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जीसैट-7सी के लिए 2563 करोड़ रुपये का अनुबंध बेंगलूर स्थित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड



के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित यह संचार उपग्रह वायुसेना के संसाधनों के लिए सुरक्षित, सुदृढ़ और निबंध संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने

में मदद करेगा। इससे वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।

वहीं, वरुणास्त्र टॉरपीडो की खरीद के लिए हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के

साथ 1543 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। यह पोत से प्रक्षेपित किया जाने वाला स्वदेशी भारी वजन का पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है। इसे नौसेना की विज्ञान और

प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने विकसित किया है। यह उन्नत दिशा परिवर्तन क्षमता से लैस है और लंबी दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है। इससे नौसेना की

पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी। दोनों अनुबंधों पर 15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण विभाग के अपर सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अंबारामु की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और देश की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के अनुरूप हैं।

अनजान कॉल की पहचान आसान स्क्रीन पर दिखेगा नाम और नंबर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: मोबाइल फोन पर आने वाली अनजान कॉल की पहचान आसान बनाने के लिए 1 नवंबर 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा लागू करने की तैयारी है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 4जी और 5जी मोबाइल नेटवर्क पर यह सुविधा अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम और नंबर दिखाई देगा। यदि कॉल करने वाले का नंबर फोन की संपर्क सूची में सेव है, तो वही नाम प्रदर्शित होगा। नंबर सेव नहीं होने पर सिम लेते समय दर्ज कराया गया नाम स्क्रीन पर दिखेगा। इस सुविधा के लिए मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अलग से सेवा सक्रिय नहीं करनी होगी।

इस व्यवस्था के तहत दूरसंचार कंपनियां अपने ग्राहकों के नाम और मोबाइल नंबर को जोड़ने वाला डेटाबेस तैयार करेंगी। कॉल आने पर इसी डेटाबेस से नाम लेकर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हालांकि, जिन ग्राहकों ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रतिबंधित करने की सेवा ली है, उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय कॉल आने पर स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय कॉल लिखा दिखाई दे सकता है। व्यावसायिक और बल्क सिम कनेक्शन इस्तेमाल करने वालों को पंजीकृत व्यापार नाम या ट्रेडमार्क प्रदर्शित कराने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए संबंधित दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल यह व्यवस्था 4जी और 5जी या उससे नई पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क पर लागू करने की तैयारी है। 2जी, 3जी और लैडलाइन नेटवर्क के लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा।

खास-खाबरें

देश का निर्यात सितंबर में 23 फीसदी बढ़कर 44.4 अरब डॉलर पर पहुंचा

नई दिल्ली। दीपावली के पहले निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। देश का वस्तु निर्यात सितंबर में सालाना आधार पर 23.04 फीसदी बढ़कर 44.40 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि व्यापार घाटा घटकर 30.21 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 36.08 अरब डॉलर था। वस्तु व्यापार घाटा भी कम होकर 30.21 अरब डॉलर रह गया है, जो एक साल पहले 33 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया कि इस दौरान आयात आट फीसदी बढ़कर 69.08 अरब डॉलर से बढ़कर 74.61 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे व्यापार घाटा भी घटकर 30.21 अरब डॉलर रह गया है, जो सितंबर, 2025 में 33 अरब डॉलर था। मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान निर्यात 18.51 फीसदी बढ़कर 259.89 अरब डॉलर हो गया है। आयात 16.31 फीसदी बढ़कर 437.53 अरब डॉलर रहा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि अगर आप सितंबर माह में वस्तु निर्यात को देखें, तो यह 44.40 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो पिछले साल के सितंबर की तुलना में 23.04 फीसदी अधिक है। अग्रवाल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और कृषि उत्पादों की बढ़ी हुई शिपमेंट ने इस वृद्धि को सहारा दिया है।

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.21 फीसदी बढ़कर 13.38 लाख करोड़ रुपये हुआ

नई दिल्ली। कॉरपोरेट कर संग्रह में अच्छी वृद्धि से चालू वित्त वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से 14 अक्टूबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.21 फीसदी बढ़कर करीब 13.38 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 20.58 फीसदी बढ़कर 5.99 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जबकि गैर-कॉरपोरेट कर (व्यक्ति, कंपनियों और हिंदू अविभाजित परिवारों) द्वारा चुकाया जाने वाला कर) संग्रह 5.83 फीसदी बढ़कर करीब 6.92 लाख करोड़ रुपये रहा। आयकर विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) संग्रह 52 फीसदी बढ़कर 46,840 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में कर 'रिफंड' (कर वापसी) सालाना आधार पर 24.22 फीसदी बढ़कर 2.65 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा सकल आधार पर प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 14 अक्टूबर तक 15 फीसदी बढ़कर 16.03 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसमें 7.53 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर संग्रह और 8.03 लाख करोड़ रुपये का गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह शामिल है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बैंकोंक में यूके के चांसलर जॉन हीली से की मुलाकात

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैंकोंक में यूके के चांसलर ऑफ द एक्चेंजर जॉन हीली से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई महत्व मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर जारी एक प्रब्यान में बताया कि सीतारमण ने थार्डलैंड की राजधानी ब्रैकन में आईएमएफ-विश्व बैंक की सालाना बैठकों के दौरान यूके के चांसलर ऑफ द एक्चेंजर, जॉन हीली से मुलाकात की। इस दौरान सीतारमण ने पिछले 'आर्थिक और वित्तीय संवाद' के नतीजों को आगे बढ़ाते हुए, चौथे 'भारत-यूके वित्तीय बाजार संवाद', फिनटेक बैठकों और इनसे जुड़ी आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर भी चर्चा की। मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण ने साझा प्राथमिकताओं और एक रचनात्मक तथा समावेशी जी-20 प्रक्रिया की दिशा में यूके के साथ मिलकर काम करने के भारत के संकल्प को दोहराया। साथ ही सीतारमण ने उन्हें यह भी बताया कि भारत 14वें आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी) को लेकर उत्सुक है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों, ग्रीन टेक और शहर-क्षेत्र साझेदारियों में सहयोग का प्रस्ताव है। दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि अगला ईएफडी इस साल दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सीतारण का गुरुवार को बैंकोंक के सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पहुंचने पर थार्डलैंड में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल ने स्वागत किया।

आईएमएफ ने भारत की संशोधित जीडीपी गणना पद्धति का किया समर्थन

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था की गणना पद्धति का आईएमएफ ने समर्थन दिया है। आईएमएफ ने गुरुवार को कहा कि भारत की संशोधित जीडीपी गणना की पद्धति सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और आईएमएफ की सलाह से पूरी तरह मेल खाती है। आईएमएफ के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने बैंकोंक में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष में संशोधन 'स्वागत योग्य कदम' है। उन्होंने कहा कि भारत ने जीडीपी गणना पद्धति में संशोधनों को समझाने के लिए एक टिप्पणी भी जारी की है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आईटी-ऑटो शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिला

समर्थन निफ्टी 374 अंक बढ़ा

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11 प्रतिशत चढ़कर 74,316 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 374 अंक यानी 1.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,997 अंक पर पहुंच गया। बाजार में आईटी और ऑटो कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि सरकारी बैंकों के शेयरों में बिकवाली रही।

बाजार में तेजी के पीछे कई प्रमुख कारण रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक डॉलर से अधिक की गिरावट ने भारतीय बाजार को समर्थन दिया। कच्चा तेल सस्ता होने से भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों को फायदा मिल सकता है। आईटी क्षेत्र के प्रमुख शेयरों में भी लगातार तीसरे कारोबारी दिन बढ़त दर्ज की गई। टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों से निवेशकों का रुझान इस क्षेत्र की ओर बढ़ा।



इसके अलावा, वैश्विक बाजारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी कंपनियों

के शेयरों में गिरावट के बीच विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार की ओर

वॉट्सऐप का नया फीचर, बिना खाता बनाए भी कॉल में जुड़ सकेंगे लोग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वॉट्सऐप ने उपयोगकर्ताओं के लिए गेस्ट कॉलिंग नाम का नया फीचर शुरू किया है। इसकी मदद से ऐसे लोगों को भी वॉट्सऐप कॉल में शामिल किया जा सकेगा, जिनका इस मंच पर खाता नहीं है और जिन्होंने अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इसका ऐप इंस्टॉल नहीं किया है। इसके लिए कॉल शुरू करने वाला व्यक्ति आमंत्रण लिंक भेज सकेगा, जिसके

माध्यम से अतिथि सीधे कॉल में शामिल होने का अनुरोध कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत अतिथि अपने मोबाइल या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में लिंक खोलकर कॉल से जुड़ सकते हैं। उन्हें अलग से ऐप डाउनलोड करने या खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। गेस्ट कॉलिंग में उपयोगकर्ताओं को कई प्रमुख सुविधाएं भी मिलेंगी। वे कॉल के दौरान हाथ उठाने, स्क्रीन साझा करने और इमोजी के माध्यम से

प्रतिक्रिया देने जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

वॉट्सऐप के अनुसार, गेस्ट कॉल भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेगी। इसका मतलब है कि बातचीत की कॉल में शामिल लोगों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकेगा। सुरक्षा के लिए, इसमें प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी दी गई है। लिंक खोलने के बाद अतिथि को पहले प्रतीक्षा कक्ष में जाना होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व करें युवा: पीयूष गोयल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में दक्षता हासिल कर भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने गुरुवार को एसआरसीसी शताब्दी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 'विकसित भारत की राह' विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि विनिर्माण, तकनीकी विकास और कौशल प्रशिक्षण में निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य देश के 1.4 अरब नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसके लिए युवाओं को बदलती तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर जोर, उभरती प्रौद्योगिकियों

साइबर सुरक्षा और कौशल विकास को बताया रोजगार का आधार

बड़े भाषा मॉडल और अन्य एआई प्रणालियों को ऐसे व्यावहारिक उपकरणों में विकसित करना जरूरी है, जिनका उपयोग व्यवसायों और आम नागरिकों के लिए उपयोगी हो। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यापार प्रक्रियाएं भारत को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बनाती हैं। नई तकनीकों को अपनाने और विनिर्माण का विस्तार करने से रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। उन्होंने युवाओं से केवल नई तकनीक का उपयोग करने तक सीमित न रहने,

बल्कि उसके विकास और व्यावहारिक अनुप्रयोग में भी नेतृत्व करने की अपील की। गोयल ने उद्यमशीलता और नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्टार्टअप संस्थापक जोखिम उठाकर चुनौतियों के समाधान तलाशते हैं। युवाओं की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को मजबूत कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा आबादी, बड़ा घरेलू बाजार और उद्यमशीलता की भावना भारत को अगले 20 से 25 वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी निवेश के लिए आकर्षक बनाती हैं। इससे नए बाजारों में विस्तार और मौजूदा ग्राहकों के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिल रही है। साथी अधिकारी अपर्णा अय्यर के अनुसार, दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन 16.5 प्रतिशत रहा, जो पिछली तिमाही से 0.5 प्रतिशत अधिक है।

जियो प्लेटफॉर्मर्स का आईपीओ 21 से खुलेगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्मर्स का आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खुलेगा। कंपनी इस निर्गम के माध्यम से लगभग 30,213 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। प्रति शेयर मूल्य दायरा 1065 रुपये से 1119 रुपये तय किया गया है।

कंपनी की ओर से दाखिल रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, बड़े संस्थागत निवेशकों यानी एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तारीख 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आम निवेशक 21 से 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इस निर्गम के साथ जियो प्लेटफॉर्मर्स देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी बन जाएगी। इससे पहले 2024 में

30 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

1065 से 1119 रुपये प्रति शेयर होगा मूल्य दायरा

हुंडई मोटर इंडिया का 27,858 करोड़ रुपये का आईपीओ सबसे बड़ा था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्मर्स ने 19 जून को प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए थे। इसके बाद 28 अगस्त को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से मंजूरी मिली। कंपनी ने

14 अक्टूबर को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया। जियो प्लेटफॉर्मर्स में रिलायंस जियो का दूरसंचार और डिजिटल सेवा कारोबार शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक कंपनी के ग्राहकों की संख्या 52.44 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 48.82 करोड़ थी। आईपीओ से पहले दाखिल दस्तावेजों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार और जोखिम संबंधी जानकारी दी गई है।

कर्मचारियों और शेयरधारकों के लिए आरक्षण

जियो प्लेटफॉर्मर्स ने कर्मचारियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित किए हैं। इसमें कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपये तक और पात्र शेयरधारकों के लिए 2500 करोड़ रुपये तक का आरक्षण शामिल है। पात्र कर्मचारियों को आवेदन पर प्रत्येक शेयर के लिए 54 रुपये की छूट मिलेगी। आम निवेशक न्यूनतम 12 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन कर सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार, जिनके पास 14 अक्टूबर तक कंपनी के सार्वजनिक इक्विटी शेयर थे, निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन शेयरधारक आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

स्पेशल खबर

दूसरी तिमाही में कंपनी को 3200 करोड़ रुपये का लाभ, राजस्व 9.1 प्रतिशत बढ़ा; 2026 में अब तक शेयर 35 प्रतिशत दूटे

विप्रो का मुनाफा 1.4 प्रतिशत घटा, तीन महीने में 6716 कर्मचारी कम हुए

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे गुरुवार को जारी किए। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का राजस्व 9.1 प्रतिशत बढ़कर 24,752.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 22,697.3 करोड़ रुपये था। हालांकि, राजस्व में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी का शुद्ध मुनाफा 1.4 प्रतिशत घटकर 3,200.6 करोड़ रुपये रह गया। पिछले वर्ष दूसरी तिमाही में कंपनी को 3,246.2 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तिमाही के अंत में विप्रो में 2,36,328 कर्मचारी रह गए, जबकि पिछली तिमाही में यह संख्या 2,43,044 थी। इस तरह तीन महीने में कर्मचारियों की संख्या 6,716 कम हुई। पिछले 12 महीनों के आधार पर कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 13.8 प्रतिशत रही, जो पिछली तिमाही में 13.9 प्रतिशत थी। शेयर बाजार में विप्रो का प्रदर्शन भी कमजोर रहा है। गुरुवार को कंपनी का



शेयर 1.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 174.05 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, वर्ष 2026 में अब तक इसके शेयर में 34.9 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। इस दौरान निफ्टी-50 में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 1.72 लाख करोड़ रुपये है। विप्रो ने तीसरी तिमाही के लिए आईटी सेवाओं से 2.57 अरब डॉलर से 2.62 अरब डॉलर के राजस्व का अनुमान जताया है। कंपनी के अनुसार, पिछली तिमाही की तुलना में कारोबार में 1.5 प्रतिशत तक

गिरावट या अधिकतम 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों में निवेश के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। इससे नए बाजारों में विस्तार और मौजूदा ग्राहकों के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिल रही है। साथी अधिकारी अपर्णा अय्यर के अनुसार, दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन 16.5 प्रतिशत रहा, जो पिछली तिमाही से 0.5 प्रतिशत अधिक है।

रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा यात्रा बीमा, 27 अक्टूबर से लागू होगा नियम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को उपलब्ध थी। काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए भी बीमा वैकल्पिक रहेगा। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशनों के आरक्षण काउंटर से टिकट लेते हैं। ऐसे यात्रियों को भी बीमा का विकल्प मिलना चाहिए। यह मामला जून 2023 में ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और हादसों की जांच के अनुसार समिति गठित करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया।

बीमा से जुड़ी प्रमुख बातें

रेल यात्रा बीमा के तहत ट्रेन के पटरी से उतरने, दो ट्रेनों की टक्कर, आतंकवादी हमले या अन्य अग्रिय घटनाओं में यात्री की मृत्यु, अंगभंग अथवा गंभीर चोट लगने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा राशि मिल सकती है। मृत्यु या पूर्ण विलीनगता की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का कवर उपलब्ध हो सकता है। चोट लगने पर निर्धारित निमियों के अनुसार सहायता या उपचार खर्च दिया जा सकता है। हालांकि, आत्महत्या के प्रयास, जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहुंचाने या निर्धारित अपवादों के अंतर्गत आने वाली घटनाओं में बीमा लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को यह सुविधा लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर निर्देश जारी किया।